(घ) यदि हां, तो क्या छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की सेवा को बिलासपुर से झारसुगुडा तक बढ़ाया जाएगा?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजय सिंह): (क) और (ख) जी हां, रायगढ़ के रास्ते हवड़ा और भोपाल के बीच चलने वाले दूसरे दर्जे के सीधे शयनयान को छोड़कर।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्यकरण

*355. **श्री राम नरेश यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्वरूप तथा उसके कार्यकरण की जांच करने के लिए गठित अनेक जांच समितियों और आयोगों ने इस संबंध में आमूल परिवर्तन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों का गठन कब किया गया था और उन्होंने सरकार को अपनी सिफारिशें कब प्रस्तुत कीं;

(ग) सरकार द्वारा उनके संबंध में अभी तक कोई निर्णय न लिये जाने के क्या कारण है; और

(घ) क्या निकट भविष्य में इस संबंध में कोई निर्णय ले लिये जाने की संभावना है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) इस प्रकार की गत समिति "दिल्ली-विकास प्राधिकरण के कार्यकरण की गहन जांच करने के लिए विशेषज्ञों की समिति" थी। यह 25 अक्तूबर, 1977 को गठित की गई थी और इसने अपनी रिपोर्ट जून, 1978 में दी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने संगठनात्मक ढांचे का अध्ययन करने तथा इसमें सुधारों का सुझाव देने के लिए 1984 में मेसर्स टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेस को भी कार्य सौंपा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1986 में प्रस्तुत की। सातवीं लोकसभा की प्राकलन समिति ने वर्ष 1984-85 की अपनी 85वीं रिपोर्ट में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया था। दिल्ली के ढांचे के पुनर्गठन संबंधी समिति (1987 में गठित) में दिसम्बर, 1989 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में दिल्ली विकास प्राधिकरण के संबंध में टिप्पणियां की।

इन सब समितियों की सिफारिशों में इस बात पर बल दिया गया था कि दिल्ली विकास प्राधिकरण से असम्बद्ध कार्य निकाल दिये जायें और इसे अपने प्रमुख कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए अर्थात् दिल्ली की बृहत योजना तैयार करना और बृहद योजना के अनुसार दिल्ली का विकास करना।

उपर्युक्त सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में सरकार ने 1987 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन का निर्णय लिया था। तथापि, दिल्ली के ढांचे के पुनर्गठन संबंधी समिति 1987 के अंत में गठित की गई थी और दिल्ली विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन के संबंध में निर्णय पर कार्यवाही नहीं की गई थी। दिल्ली के ढांचे संबंधी समिति की सिफारिशें फिलहाल गृह मंत्रालय के विचाराधीन हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन पर आगे कार्रवाई अब दिल्ली के भावी ढांचे पर निर्णय को देखते हुए की जायेगी।

*356 *Transferred to the 28th May 1990.*

Complaints regarding sinking of DDA Flats

*357. DR. YELAMANCHILI SIVAJI : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state whether Government have received any complaints recently re-

garding sinking down of DDA flats in Delhi; if so, what steps have been taken to redress the same ?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN) : Yes, Sir.

Such complaints were last received from Maurya Enclave, Pitampura on the 7th May. Senior Officers of DDA visited the site the same day and also subsequently. Lt. Governor, Delhi, personally inspected the site on the 10th May. Settlement had occurred near the 20 ft. deep sewer line constructed by DDA during the years 1975-78, which runs at a distance of aro und 3 ft. from the plot. In house No. KP-283, a part of front compound wall had Settled by 3" there was settlement of floor in the front setback and some cracks in the walls. Reasonable compensation has been promised to the owner of the house who has been advised to keep DDA informed of the repair works being carried out by him.

Survey report on construction workers

*358 SHRIMATI KAMLA SINHA : Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the recent survey Report on construction workers specially the plight of women workers, conducted by the Directorate of labour Bureau ;

(b) if so, what are the main features of the report; and

(c) whether Government propose to implement the various labour laws including the Equal Remuneration Act for the construction workers and if so, by when ?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN) : (a) to (c) The Labour Bureau under the Ministry of Labour had conducted a Survey to Study the Socio-Economic Conditions of Women Workers in the Building and Construction Activities in the four metropolitan cities of Delhi, Bombay, Calcutta and Madras. The main features of the report include instances of violation of Labour Laws such as Equal Remuneration Act, 1976, Minimum Wages Act, 1948 and various welfare measures provided in Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 etc. The report generally observes that the working conditions of women workers were adverse compared to those of male workers. Absence of legislative provisions for safety, health and welfare of construction workers including those relating to maternity benefits for female construction workers too has been high lighted in the report. The State Governments are being advised to take note of the observations in the report and to ensure proper enforcement of all Labour Laws concerning the unorganised labour.

Sugar cane development scheme in Uttar Pradesh

*359. KUMARI ALIA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to start the Sugar Cane Development Scheme in Faizabad and other district of Uttar Pradesh;

(b) if so, the details thereof and by when the scheme is proposed to be taken up;

(c) the details of the financi assistance to be provided dural 1990-91 for the purpose; and in

(d) if no assistance has been provided so far, what are the reasons therefor ?